Public

उत्पत्ति/ Genesis

नाबार्ड 1990 के दशक के दौरान भारत में इंडो-जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आईजीडब्ल्यूडीपी) की शुरुआत से वाटरशेड विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है. भागीदारी वाटरशेड विकास की संकल्पना और कार्य-प्रणाली वर्षा सिंचित क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय की उत्पादकता, उत्पादन और आजीविका की सुरक्षा को बेहतर बनाने में एक सफल पहल साबित हुई है. देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में इन पहलों को आगे इसी रूप में लागू करने के लिए और वाटरशेड विकास कार्यक्रमों की विविधता को ग्राम स्तरीय संस्थाओं और परियोजना सुविधा एजेंसियों (पीएफए) की संलग्नता के माध्यम से एकल राष्ट्रीय पहल के रूप में एकीकृत करने के व्यापक उद्देश्य के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 1999-2000 के अपने बजट भाषण में नाबार्ड में वाटरशेड विकास निधि (डब्ल्यूडीएफ़) के सृजन की घोषणा की थी. इसके अनुसरण में, नाबार्ड में कृषि मंत्रालय (एमओए), भारत सरकार और नाबार्ड प्रत्येक के द्वारा रु.100 करोड़ के अंशदान के साथ डब्ल्यूडीएफ़ का सृजन किया गया है.

NABARD has been implementing watershed development projects since inception of Indo German Watershed Development Programme (IGWDP) in India during 1990s. The participatory watershed development concept and the methodology had been proved to be a successful initiative in enhancing the productivity, production and improving livelihood security of rural community in rainfed areas.In order to further replicate the initiatives in the drought prone areas of the country, the Union Finance Minister, in his budget speech for 1999- 2000 had announced the creation of a Watershed Development Fund (WDF) in NABARD with broad objectives of unification of multiplicity of watershed development programmes into a single national initiative through involvement of village level institutions and Project Facilitating Agencies (PFAs). In pursuance thereof, WDF has been created in NABARD with a contribution of Rs.100 crore each by the Ministry of Agriculture (MoA), Government of India and NABARD.